



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

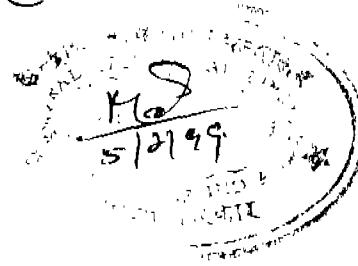
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 246]

No. 246]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 7, 1998/ कार्तिक 16, 1920

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 7, 1998/KARTIKA 16, 1920

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, ८ नवम्बर, 1998

अधिष्ठापना /

विषय :-

झारखण्ड मुकित मोर्चा रिष्वत मामले के संबंध में पी.वी. नरसिंहा राव
बनाम सरकार [सी.बी.आई/एस.पी.ई.] मामले में उच्चतम न्यायालय
द्वारा दिस ग्रस फैसले के निहितार्थों की जांच करने के लिए अंतः मंत्रालय
[सरकारी स्तर] समिति का समय बढ़ाने के संदर्भ में।

-४-४-

फा. संख्या ८१२/१४-भू-आर सम्मे. झारखण्ड मुकित मोर्चा रिष्वत मामले के संबंध में
पी.वी. नरसिंहा राव बनाम सरकार [सी.बी.आई/एस.पी.ई.] मामले में उच्चतम
न्यायालय द्वारा दिस ग्रस फैसले के निहितार्थों की जांच करने के लिए गठित अंतः मंत्रालय
[सरकारी स्तर] समिति के संबंध में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- ।, खण्ड -।,
दिनांक 25 जून, 1998 में प्रकाशित इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिष्ठापना दिनांक 25 जून,
1998 के पैराग्राफ 6 द्वारा यह नियत किया गया था कि समिति अपनी पहली बैठक
की तारीख से 2 माह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट को अंतिम स्पष्ट दे देगी।

2. समिति की पहली बैठक 9 जुलाई, 1998 को हुई थी। अतः समिति को अपनी रिपोर्ट को अंतिम स्पष्ट दिनांक 8 सितम्बर, 1998 को अध्या उससे पहले दे देना चाहिए था। ऐसा महसूस किया गया कि समिति को अपने प्रतिवेदन को अंतिम स्पष्ट देने में कुछ और समय लगेगा अतः समिति का कार्यकाल 9 सितम्बर, 1998 से दो महीने और आगे बढ़ाने हेतु इस मंत्रालय द्वारा एक समसंख्यक अधिकृत्यना दिनांक 28 अगस्त, 1998 जारी की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग - I खण्ड - I में दिनांक 29 अगस्त, 1998 को प्रकाशित हुई थी। अतः समिति को दिनांक 8-11-1998 को अध्या इस से पूर्व अपने प्रतिवेदन को अंतिम स्पष्ट देना था।

3. समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट को अंतिम स्पष्ट देने में कुछ और समय लगाए जाने की संभावना है, अतः रिपोर्ट को अंतिम स्पष्ट देने के लिए समिति का कार्यकाल 9 नवम्बर, 1998 से 2 माह की अवधि के लिए आगे और बढ़ाया जाता है।

देवराज तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 6th November, 1998

NOTIFICATION

Subject: Inter-Ministerial (Official Level) Committee to examine the implications of the Supreme Court Judgement delivered in the case of P.V. Narasimha Rao Vs. State (CBI/SPE) regarding JMM Bribery case -extension of time regarding.

No.F.8(2)/98-R&C -- Vide paragraph 6 of this Ministry's Notification of even number dated 25th June, 1998 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, dated the 25th June, 1998 regarding constitution of an Inter-Ministerial (Official Level) Committee to examine the implications of the Supreme Court Judgement delivered in the case of P.V. Narasimha Rao Vs. State (CBI/SPE) regarding JMM Bribery case, it was stipulated that the Committee will finalise its report within a period of 2 months from the date of its first meeting.

2. The first meeting of the Committee was held on 9th July, 1998. Therefore, the Committee was to finalise its report on or before 8th September, 1998. As it was felt that the Committee was likely to take some more time to finalise its report, the time for finalising the report of the Committee was extended by a further period of two months with effect from 9th September, 1998 vide this Ministry's Notification of even number dated 28th August, 1998 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section-I dated 29th August, 1998. Therefore, the Committee was to finalise its report on or before 8th November, 1998.

3. As the Committee is likely to take some more time to finalise its report, the time for finalising the report of the Committee is extended by a further period of two months with effect from 9th November, 1998.

D.R. TIWARI, Jt. Secy.

